

न्यायालय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर
समक्ष
एम०के०सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2374-दो/2012 - विरुद्ध आदेश दिनांक 25.5.12 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 256/2008-09 निगरानी

1- बालकिशन पुत्र हल्केराम चमार
2- खिलन पुत्र हलके चमार ग्राम कर्
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर --आवेदकगण
विरुद्ध

1-प्रभूलाल पुत्र सुन्दरलाल लोधी
2-हीरालाल (मृत) पुत्र बारेलाल
वारिस

अ- मलखान ब- अमरसिंह
स- शिवराज पुत्रगण हीरालाल
क- कु.भेदवती पुत्री हीरालाल
ख- श्रीमती गनेश पत्नि स्व.हीरालाल
3- असगर खां पुत्र अल्ताफ
4- सनमान पुत्र चम्मालाल दर्जी
सभी ग्राम कर् तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

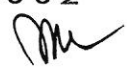
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(दिनांक 3-2 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 256/2008-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-5-12 के विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि ग्राम कर् स्थित आराजी क्रमांक 488/2 रकबा 2.877 हैक्टर काबिलकास्त भूमि का नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/ 01-02 में आदेश दिनांक 2-5-2002 से द्वारा भूमिहीनों को बन्टन किया



R

गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्र0 क0 120/2001-02 में पारित आदेश दि0 25-2-2003 से आवेदक के हित में दिया गया पट्टा निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 256/2008-90 निगरानी में पारित आदेश दि0 25-5-12 से निगरानी निरस्त कर दी गई क्योंकि अनावेदक क्रमांक-2 हीरालाल की मृत्यु होना तामील कुनिन्दा ने 23-10-10 को बताया है किन्तु 25-5-12 तक मरम्मत सवाल का आवेदन नहीं दिया है इसलिये निगरानी अवेट मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ प्रकरण में प्रथमतः विचार योग्य है कि अनावेदक क्रमांक-2 हीरालाल की मृत्यु होना तामील कुनिन्दा ने 23-10-10 को बताया है और 25-5-12 तक मरम्मत सवाल का आवेदन आवेदक के अभिभाषक ने प्रस्तुत नहीं किया है तब क्या निगरानी अवेटमेंट में समाप्त होगी ? अपर आयुक्त के प्रकरण के उन्मान में दिये गये पक्षकारों के विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में चार अनावेदक हैं जबकि अनावेदक क्रमांक 2 हीरालाल पुत्र बारेलाल प्रजापति की मृत्यु हुई है किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर संपूर्ण प्रकरण अवेट नहीं होता, क्यों कि प्रकरण में तीन अन्य पक्षकार जीवित मौजूद हैं। अतएव अपर आयुक्त द्वारा आदेश दि. 25-5-12 में लिया गया निर्णय विसंगतिपूर्ण है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि नायब तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/ 2001-02 में आदेश दिनांक 2-5-2002 से किये गये भूमि बन्टन के विरुद्ध

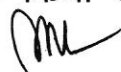


2

अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष हीरालाल पुत्र रुमाल चमार के विरुद्ध प्रभूलाल एवं अन्य 5 ने अपील क्रमांक 120/2001-02 प्रस्तुत की है , जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-2-03 से नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-5-2002 निरस्त किया गया है और जब इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष हीरालाल पुत्र रुमाल चमार निवासी कर् ने निगरानी क्रमांक 246/2009-10 प्रस्तुत की, अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2010 से निगरानीकर्ता हीरालाल के हित तक निगरानी स्वीकार की है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील क्रमांक 120/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 25-2-03 निरस्त किया है तब अपर आयुक्त द्वारा इस प्रकरण के तथ्यों को नजरबन्दाज करते हुये मात्र एकपक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण अवेटमेंट में समाप्त करके आवेदक के हितों की अनदेखी करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-5-12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर बंटन के पूर्व से कब्जा होकर खेती करते आ रहा है एवं वर्ष 2002 में भूमि आवंटित हो जाने पर स्वत्व प्राप्ति उपरांत परिश्रम करके एवं धन व्यय करके उसने उबड़-खाबड़ भूमि को समतल करके चारों ओर मेढ़ बन्धान बना लिये एवं सिंचाई के साधन ट्यूब वेल लगवा लिया तथा निवास हेतु मकान निर्माण कर रहने लगा है। आवेदक अनुसूचित जाति का है यदि उससे भूमि वापिस ले ली जाती है उसे धनहानि होने के साथ परिवार के पालन-पोषण में व्यवधान उत्पन्न हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय।

1. इन्दरसिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटित को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।



R

2. शंकरलाल वर्मा विरुद्ध म0प्र0राज्य 1984 रा0नि0128 का न्यायिक दृष्टांत है जब तक कि समुचित क्षति सिद्ध नहीं की जाती है, पट्टेदार द्वारा भूमि को सुधारने और कुओं निर्माण करने में अत्यधिक राशि व्यय की गई। सामान्यतः ऐसे आबन्तन को रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों पर गौर न करते हुये आवेदक के हित में हुये भूमि बन्तन को निरस्त करने में भूल की है एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी आदेश दिनांक 25-5-12 से मृतक के हित तक अवेट होने के तथ्य को अनदेखा करते हुये संपूर्ण निगरानी प्रकरण निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 256/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दि0 25-5-12 एवं अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा अपील क्रमांक 120/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 25-2-03 आवेदक के हित तक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 2-5-2002 से सर्वे क्रमांक 488/2 क के पट्ट तक यथावत् रखा जाता है।


(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

R